



Indian Council of World Affairs

Sapru House, Barakhamba Road

New Delhi

संगोष्ठी पेपर

“भारत की विदेश नीति: भारत-नेपाल सम्बन्ध”

प्रस्तुतकर्ता

राकेश कुमार मीना

रिसर्च फेलो , आइ. सी. डब्ल्यू. ए.

एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

“भारत की विदेश नीति: भारत-नेपाल सम्बन्ध”

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर

६ अक्टूबर, २०१६

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के संभाषणों और कार्यक्रमों में विदेश नीति के मुद्दों पर हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार हेतु परिषद् के सहयोग से रक्षा एवं स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर में ६ अक्टूबर, २०१६ को भारत की विदेश नीति: भारत-नेपाल सम्बन्ध विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम, डॉ श्री भगवान सिंह (कार्यक्रम संयोजक), आचार्य, रक्षा एवं स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और परिचय करवाया। महाविद्यालय के परिसर में आयोजित इस संगोष्ठी में आमंत्रित अतिथियों के अलावा काफी संख्या में विद्यार्थी, शोधार्थी और मीडियाकर्मी भी उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र में मंच पर अध्यक्ष के रूप में प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, मुख्य अतिथि के रूप में राजदूत श्री अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, भारत सरकार, नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर एम. के. सगोच- कमान्डेंट, जी. आर. डी., गोरखपुर तथा इनके अतिरिक्त महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह एवं डॉ श्री भगवान सिंह भी मंचासीन थे।

उद्घाटन सत्र में प्रारंभ में माँ सरस्वती, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्ज्वन किया गया। इसके बाद मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत संयोजक द्वारा कार्यक्रम की प्रस्ताविकी प्रस्तुत की गयी और मुख्य अतिथि राजदूत श्री अचल मल्होत्रा को मुख्य उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया।

राजदूत अचल मल्होत्रा ने अपने उद्बोधन को प्रारंभ करते हुए कहा कि वर्तमान में विदेश नीति पर विमर्श अब दिल्ली केन्द्रित न होकर प्रान्त स्तर (जैसे गोरखपुर) पर जा रहा है। और साथ ही साथ यह आम लोगों के मध्य धीरे धीरे विमर्श का विषय बन रहा है। उन्होंने आई सी डब्ल्यू ए का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने विदेश नीति का अर्थ बताते हुए इसे राष्ट्रों का स्वयं के हितों की रक्षा करना बताया। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जैसे, पंचशील और अहस्तक्षेप, लेकिन कभी कभी हमें अपने हितों के लिए १९७१ (बांग्लादेश) और १९८७ (श्री लंका) जैसे भी कदम उठाने पड़ते हैं। भारत ने यद्यपि कभी लोकतंत्र का निर्यात नहीं किया लेकिन जहाँ लोकतंत्र पनप रहा है उसे सदैव समर्थन दिया है। अभी हाल ही भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के खातिर सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसे पूरे विश्व ने सही और न्यायसंगत ठहराया। भारत कभी भी वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता करते समय किसी प्रकार की शर्त नहीं थोपता लेकिन वही चीन ऐसा करता है।

कूटनीति और देश के चहुमुखी विकास में काफी गहरा सम्बन्ध है और वर्तमान सरकार इसे समावेशी विकास के रूप में प्रयुक्त करने में प्रयासरत है। इस समावेशी विकास में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों/नीतियों के माध्यम से बाहरी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। राजदूत मल्होत्रा ने कूटनीति के केवल राजनितिक पहलु को पर्याप्त न मानते हुए वर्तमान दौर को देखते हुए आर्थिक कूटनीति को काफी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसी देश की सशक्त कूटनीति में राजनितिक कूटनीति और आर्थिक कूटनीति का समायोजन होता है। पहले पडौस की नीति की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति क्षेत्र में प्रगति, विकास और सुख शांति के लिए काफी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्रीय अंतर्सम्बन्धता और अंतरक्षेत्रीय संगठन सार्क की क्षेत्र के भीतर और बाहर संभावित बढ़ती भूमिकाओं पर भी बल

दिया। उन्होंने कहा कि अभी भूटान, बांग्लादेश और श्री लंका के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सेना और कट्टरपंथी समूहों और नेताओं हस्तक्षेप होने के कारण यहाँ सदैव राजनितिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। जिसके कारण भारत आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे समस्याओं से जूझता रहा है। भारत के वृहद पड़ोस में आसियान आता है जिसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। १९९० में शुरू की गयी लुक ईस्ट पालिसी का निरूपण अभी की सरकार ने एकट ईस्ट पालिसी के रूप में किया है जो कि पहले से एक कदम आगे है। इसके लिए भारत एशिया प्रशांत में कई क्षेत्रों में भूमिका निभाने के लिए अवसरों की तलाश में है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ब्ल्यू इकोनोमी में भी भारत के लिए सुनहरे अवसर हैं। इस क्षेत्र में भारत अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोरिशस और शेसेल्स के साथ रिश्ते बाधा रहा है। इस क्षेत्र में भारत के उद्देश्य मुख्यतया- संसाधनों का दोहन, सामुद्रिक सुरक्षा, समुद्री दस्यु, चीन के समक्ष प्रतिरोध जताने इत्यादि हैं। वर्तमान में पूरा विश्व यह मानता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वही चीन भी इस ओर वृद्धि कर रहा है लेकिन लोग कई बार उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं, पर भारत के प्रति ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में विश्व व्यवस्था में एक वैश्विक करता के रूप में भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान दौर में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि भारत की क्षमता देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में उसकी स्थायी सदस्यता होनी चाहिए।

भारत नेपाल संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के सम्बन्ध क्षेत्र में अनूठे और विशिष्ट हैं लेकिन ये कभी भूटान की तरह एक मॉडल स्थापित नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या रूकावट है इस पर हमें सोचना चाहिए। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास का बढ़ना- नेपाल में कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी भारत विरोधी बयान देते हैं और मधेश समस्या भी एक कारक रही है। १९५० की शांति और मैत्री संधि से दोनों देशों के सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए और इससे नेपाल को आर्थिक सहायता में सहूलियत भी मिलने लगी परन्तु नेपाल द्वारा बार बार चीन का कार्ड इस्तेमाल करने से संबंधों में अंतर आया है।

अन्तः उन्होंने कहा कि विदेश नीति में अब अकादमिक जगत के विचार विमर्श को समावेशित किया जा रहा है जो कि विदेश नीति निर्माण और निर्धारण में काफी उपयोगी है।

गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर एम. के. सगोच ने गोरखा सेना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि वे नेपाल जाकर युवकों को गोरखा सेना में शामिल करने का काम करते हैं। उन्होंने इस बात के इतिहास का जिक्र किया कि नेपाल के गोरखा कैसे भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्होंने गोरखा सेना को भारत नेपाल संबंधों में रक्षा कूटनीति के आयाम के रूप में बताया। गोरखा जिले की स्थापना नरेश पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। १८१४-१५ में आंग्ल युद्ध के बाद सगौली संधि हुई जिसमें ब्रिटिश गोरखा सेना का प्रावधान बना। सन १८८५ में भारत को यह छूट मिली कि वह अपने तरीके से गोरखाओं को शामिल करे और इसके लिए दो डिपो बने एक गोरखपुर में और दूसरा दार्जिलिंग में। गोरखा सैनिकों का हर युद्ध में अच्छा प्रदर्शन रहा जिसके कारण इनकी मांग रहती थी। १९४७ में गोरखा सेना को लेकर एक करार हुआ। जिसके तहत गोरखा की १० रेजिमेंट भारत में, ४ रेजिमेंट इंग्लैंड के लिए परन्तु पाकिस्तान को कोई रेजिमेंट नहीं मिली, संभवतया इसका कारण धर्म रहा हो। लेकिन अंत में सभी ने भारतीय सेना में शामिल होने की बात कही। वही भारतीय सेना ने इन गोरखा सैनिकों भारत में नेपाल से ज्यादा वेतन देने की बात भी कही। इस साल गोरखा सेना के भारतीय सेना में २०० वर्ष (१८१५-१६) पुरे होने पर द्वितीय स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है।

गोष्ठी के अध्यक्ष प्रो राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय ने विदेश नीति और भारत नेपाल संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि भारत दक्षिण एशिया और अन्य बाहरी देशों के साथ कैसे विदेश नीति का निर्धारण करे। इसके लिए राष्ट्रीय हित का संवर्द्धन सर्वोपरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के मामले में सत्तारूढ़ सरकार का हित पोषित होने के बजाय देश के हितों का पोषण जरूरी है। उन्होंने सीमा पर व्यवस्थित प्रबंधन करने की बात कही, सीमा का प्रबंधन आवश्यक है जिससे दोनों देशों के हित सुरक्षित रहे। इससे सीमा पर होने वाली अवैध आवाजाही पर भी रोक लगेगी। पाकिस्तान जैसे देशों से सीमापार आने वाले आतंकवाद पर भी इससे लगाम कसी जा सकती है। आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए भारतीय विदेश नीति में engage और enlarge के सिद्धांत को अपनाया जा सकता है।

भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के मध्य एक बड़ी चुनौती चीन है जो कि हाल ही के वर्षों में ज्यादा बढ़ी है। वही दूसरी ओर यदि नेपाल में राजनितिक अस्थिरता ज्यादा बढ़ती है तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। १९७५ में भारत में सिक्किम के विलय के बाद नेपाल भारत के इस कदम से काफी सहम गया था और उसने अपने पूरे क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित कर दिया था। अभी हाल के दौर में दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कैसे भारत विरोधी तत्वों से लड़ा जाये, जिसमे सीमा पार जाली मुद्रा और तस्करी को रोकना अति आवश्यक है। मधेश की समस्या नेपाल के नए संविधान से जुड़ी हुई है और यह भारत को भी प्रभावित कर रही है। नेपाल में निरंतर चल रही राजनीतिक अस्थिरता ने भी दोनों देशों के संबंधों पर असर डाला है।

इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी और संचार व्यवस्था को देखकर पड़ोसी देश भारत की तरफ आकर्षित हो रहे है। वही भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाते हुए उन्हें engage करने की जरूरत है।

अपराहन में तकनीकी सत्र प्रारंभ हुए जिनकी अध्यक्षता डॉ बलवान सिंह ने की। प्रथम वक्ता के रूप में डॉ राकेश कुमार मीना (अनुसंधान अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्) ने वर्तमान में भारत नेपाल संबंधों पर अपने विचार तथा परिषद् के कार्य और लक्ष्यों के बारे में भी बताया। डॉ मीना ने नेपाल में विगत वर्ष में नये संविधान की घोषणा के बाद भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में कैसे उतार चढ़ाव आये इसका वर्णन किया। उन्होंने अभी हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल की भारत यात्रा का वर्णन किया और बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संबंधों को सामान्य और प्रगाढ़ करना है जिसमे पूर्व नेपाल प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के काल में रिश्तों में कड़वाहट आ गयी थी। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी से दहाल की मुलाकात हुई और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। मोदी का पुनः इस बार भी कहना था कि नेपाल अपने संविधान में इस प्रकार संशोधन करे कि वह समावेशी संविधान बने। डॉ मीना ने नेपाल द्वारा चीन और भारत के साथ व्यापार की व्यवहारिकता पर भी अपनी राय रखी और कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां चीन नहीं भारत के साथ व्यापार के अनुकूल है। अपनी बात कहते हुए डॉ मीना ने गोरखपुर की भौगोलिक अवस्थिति को काफी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह दोनों देशों के मध्य एक गेटवे है जहाँ भारत नेपाल अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा सकती है। जहाँ दोनों देशों के शोधार्थी और प्रबुद्धजन शोध और अध्ययन का कार्य कर सकते है। विश्व मामलों की भारतीय परिषद् के एक थिंक टैंक के रूप में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा 1943 में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी अधिनियम 1860 के पंजीकरण के अंतर्गत एक गैर - सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति आईसीडब्ल्यूए के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद् के मुख्य लक्ष्य हैं- अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन, अनुसंधान, विचार विमर्श, व्याख्यान, विनिमय के माध्यम से अन्य संगठनों के साथ विचार और जानकारी की भीतर और बाहर भारत इसी तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं। सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रति भारतीय नीति पर चर्चा करने और अध्ययन करने के लिए सेमिनारों की व्यवस्था करें। उन्होंने विदेश नीति पर हिंदी में विचार विमर्श करने के विदेश मंत्रालय के कदम की महत्वता को स्पष्ट किया। विदेश नीति पर हिंदी में वाद विवाद, शोध, लेख, पुस्तक, सेमिनार आदि को परिषद् द्वारा प्रोत्साहित करने की बात कही।

इसके अलावा गोष्ठी में गोरखपुर के आस पास के जिलों से लगभग ४० प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने भारत नेपाल संबंधों के विविध पहलुओं पर अपने अपने शोध पत्र पढ़े। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य ने महाविद्यालय की गोरख पीठ द्वारा स्थापना का इतिहास बताया। उन्होंने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों को गोष्ठी में आने के लिए धन्यवाद दिया।

डॉ राकेश कुमार मीना, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, सप्रू हाउस, नई दिल्ली.